न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 30/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

इलाहाबाद बैंक, सीकर।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

मैसर्स ग्लोसिरियम, एफ–27 औद्योगिक क्षैत्र, सीकर
प्रो. महेन्द्र सिंह पुत्र डालूराम, जाति जांगिड़, निवासी झींगर छोटी, तहसील व जिला सीकर राजस्थान।

ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 17 अप्रैल, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री नानूराम बुरानियां द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी मैसर्स ग्लोसिरियम, एफ–27 औद्योगिक क्षैत्र सीकर प्रो. महेन्द्र सिंह पुत्र डालूराम को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में ग्राम झींगर छोटी, तहसील व जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 1243/875 रकबा 0.10 है. व उसमें बने समस्त कच्चा पक्का निर्माण मशीनरी आदि, जिसके पूर्व में दुर्गाप्रसाद, पश्चिम में जगमालपुरा आम सड़क, उत्तर में रघुनाथप्रसाद जांगिड़, दक्षिण में भूमि खसरा नम्बर 1244/875 डालूराम जांगिड़, को बंधक रखकर 34,40,000/–रूपये (अक्षरे रूपये चौंत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 15.07.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **15.07.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **मैसर्स ग्लोसिरियम, एफ–27 औद्योगिक क्षैत्र सीकर प्रो. महेन्द्र सिंह पुत्र डालूराम** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **ग्राम झींगर छोटी, तहसील व जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसारा नम्बर 1243/875 रकबा** 0.10 **है. व उसमें बने समस्त कच्चा पक्का निर्माण मशीनरी आदि, जिसके पूर्व में दुर्गाप्रसाद, पश्चिम में जगमालपुरा आम सड़क, उत्तर में रघुनाथप्रसाद जांगिड़, दक्षिण में भूमि खसरा नम्बर 1244/875 डालूराम जांगिड़,**, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः 17 **अप्रैल, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner